

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3639

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर देने के लिए

एच-1 बी वीजा

3639. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यूएसए द्वारा पारित और 24 जून, 2020 से प्रभावी एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारतीयों के लिए एच-1 बी वीजा के निलंबन की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) भारतीयों द्वारा वर्ष 2017 से अब तक एच-1 बी वीजा प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन किए गए हैं और कितने वीजा प्रदान किए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने इस उपाय पर फिर से विचार करने के लिए यूएस प्रशासन को मनाने के लिए कोई प्रति-उपाय और रणनीति बनाई है; और
- (ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) अमेरिकी राष्ट्रपति की 22 जून 2020 की उद्घोषणा के अनुसार गैर-आप्रवासी वीजा धारकों और उनके परिवारों की कुछ श्रेणियों के प्रवेश को 31 दिसंबर 2020 (31 मार्च 2021 बढ़ाया गया है) तक निलंबित कर दिया था। यह उद्घोषणा विशेष रूप से भारत या किसी एक देश के लिए नहीं है।

(ग) वर्ष 2017, 2018 और 2019 में अमरीका सरकार द्वारा जारी किए गए एच-1 बी वीजा की कुल संख्या में से भारतीय नागरिकों को जारी किए गए एच-1 बी वीजा का हिस्सा सहित एच-1 बी वीजा के संबंध में ब्योरा निम्नानुसार है:

एच-1 बी वीजा	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
भारतीय नागरिकों को जारी	129,097	125,528	131,549
जारी किए गए कुल एच-1 बी वीजा	179,049	179,660	188,123
भारतीय नागरिकों को जारी किए गए वीजा का % हिस्सा	72.1%	69.9%	69.9%

स्रोत : यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अनुसार, अमरीका सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच जारी किए गए कुल एच-1 बी वीजा में से 69.9 से 72.1% भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार लोगों के बीच आपसी संबंधों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में उन्नति और विकास के लिए भारतीय कुशल पेशेवर लोगों के योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय पेशेवर लोगों की आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ गहन बातचीत में लगी हुई है। इन मुद्दों को 7 जुलाई 2020 को हुए भारत-अमरीका विदेश कार्यालय परामर्श और 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हुई 2+2 भारत-अमरीका मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान भी उठाया गया था।
